सिद्धार्थ शंकर राय

सिद्धार्थ शंकर रे (20 अक्टूबर 1920 - 6 नवंबर 2010) पश्चिम बंगाल के एक भारतीय वकील , राजनयिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे । अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई पदों पर काम किया , जिनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री (1972-77), केंद्रीय शिक्षा मंत्री (1971-72), पंजाब के राज्यपाल (1986-89) और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत (1992) शामिल हैं। -96). एक समय वह कांग्रेस पार्टी के मुख्य संकटमोचक थे।

जीवनी

रे का जन्म एक बंगाली बैद्य परिवार में हुआ था । रे के पिता, सुधीर कुमार रे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और उनकी माँ अपर्णा देवी , बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास की बड़ी बेटी थीं और बसंती देवी इंग्लैंड में पली-बढ़ीं। . रे की बहन न्यायमूर्ति मंजुला बोस (1930-2016) हैं जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश थीं ; पद्मा खस्तागीर के साथ, वह कलकत्ता उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीशों में से एक थीं। रे का संबंध भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुधी रंजन दास और बंगाल के पूर्व महाधिवक्ता और वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य सतीश रंजन दास से भी था ।

रे ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के मित्रा इंस्टीट्यूशन , भवानीपुर शाखा, कलकत्ता, प्रेसीडेंसी कॉलेज , कलकत्ता और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अध्ययन किया । कॉलेज और विश्वविद्यालय में , वह खेल और राजनीति दोनों में सक्रिय थे। 1941 में, उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय संस्थान चुनावों में छात्र अवर सचिव के रूप में चुना गया और समय-समय पर उन्हें छात्र सहायता कोष , वाद-विवाद, खेल और सामाजिक सहित विभिन्न विभागों का प्रभारी बनाया गया। वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज यूनियन के वाद-विवाद सचिव और बाद में महासचिव भी रहे। एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज क्रिकेट टीम की कप्तानी की। वह 1944 में इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। उन्होंने लगातार तीन सीज़न में तीन दोहरे शतक और 1000 रन बनाए थे। वह कलकत्ता में कालीघाट क्लब के लिए खेलने वाले एक उत्सुक फुटबॉलर भी थे। वह इस खेल में यूनिवर्सिटी ब्लू थे और अंतर-विश्वविद्यालय मैचों में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते थे। 1939 में, वह विजयी प्रेसीडेंसी कॉलेज फुटबॉल टीम के कप्तान थे , जिसने इलियट और हार्डिंग बर्थडे शील्ड्स दोनों जीते थे। उन्हें लॉन टेनिस और टेबल टेनिस में भी रुचि थी।

बाद में रे को 1947 में ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ इनर टेम्पल , लंदन द्वारा बार में बुलाया गया । लंदन में रहते हुए उन्होंने इंडियन जिमखाना क्लब के लिए क्रिकेट खेला ।

कैरियर

1946 में इंग्लैंड से लौटने पर , रे न्यायमूर्ति रामप्रसाद मुखर्जी के कनिष्ठ के रूप में कलकत्ता बार में शामिल हो गए , जो बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) बने। 1954 में वह कलकत्ता में केंद्र सरकार के तीन कनिष्ठ वकीलों में से एक बने ।

1957 में उन्हें भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में चुना गया , जिसे उन्होंने भारी बहुमत से जीता और डॉ. बिधान चंद्र रॉय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के सबसे कम उम्र के सदस्य बने । उन्हें कानून और जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। हालाँकि , एक वर्ष के बाद , उन्होंने डॉ. बिधान चंद्र रॉय के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए अपने मंत्री पद और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 1962 में , वह एक स्वतंत्र विधायक के रूप में भवानीपुर सीट से फिर से चुने गए। 1967 में वह फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उस वर्ष चौरंगी से विधायक चुने गए , जिसे उन्होंने अगले राज्य चुनाव में बरकरार रखा । 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो रे इंदिरा गांधी के गुट के पक्ष में चले गये । 1969 से 1971 तक, वह दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता थे। 1971 के भारतीय आम चुनाव में , उन्होंने रायगंज सीट जीती और इंदिरा गांधी के तहत शिक्षा और युवा सेवाओं के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने । वह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे ।

1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस (आर) की जीत के बाद , वह एक उपचुनाव में मालदाहा सीट से चुने जाने के बाद 20 मार्च 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे। [10] उनके प्रशासन को युद्ध से भागकर पूर्वी पाकिस्तान से आए दस लाख से अधिक शरणार्थियों के पुनर्वास और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किए गए बंगालियों के नरसंहार के अभियान की भारी समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने राज्य में माओवादी विद्रोहियों पर कार्रवाई की भी निगरानी की । उनके शासनकाल की विशेषता सीपीआई (एमएल) (जिसमें ज्यादातर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र शामिल थे) और अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थकों के खिलाफ व्यापक राजनीतिक हिंसा थी , जिसमें अक्सर राज्य पुलिस बल द्वारा राजनीतिक हत्याएं और न्यायेतर हत्याएं शामिल थीं। *1951 के कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम* की धारा 47(सी) के तहत , रे ने राज्यपाल को 22 मार्च 1972 से कलकत्ता की कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली मेयर परिषद को प्रभावी ढंग से भंग करते हुए, कलकत्ता नगर निगम को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत करने की अनुमति दे दी। उनके कार्यकाल के दौरान मेयर पद के लिए कोई और चुनाव नहीं हुआ। रे ने 1973 के *पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , जिसने पहले से मौजूद* 4-स्तरीय पंचायत प्रणाली [बीएन] को वर्तमान 3-स्तरीय पंचायत प्रणाली में बदल दिया । इस प्रणाली को 1992 में भारत के संविधान में 73वें संशोधन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था। 1973 का *पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम* उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। हालाँकि, उन्होंने नक्सलियों और कम्युनिस्टों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा बढ़ने के डर से पंचायत चुनाव कराने से इनकार कर दिया । रे ने अपने ही कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केएन वांचू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था [15] और रिश्वत लेने के आरोप में अपने ही बिजली मंत्री सुनीति चट्टराज को बर्खास्त कर दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान , दक्षिण कोलकाता के गार्डन रीच में एक नया जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया और कोलकाता मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ।

कांग्रेस (आर) के राज्य में अगला चुनाव सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन से हारने के बाद , राज्य में कांग्रेस की चुनावी हार के लिए रे को व्यापक रूप से दोषी ठहराया गया था।

चूंकि रे 1978 में पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अपने नामांकित उम्मीदवार कासु ब्रह्मानंद रेड्डी के खिलाफ खड़े हुए थे, इसलिए 1980 में सत्ता में वापस आने के बाद इंदिरा गांधी ने रे को पार्टी से अलग कर दिया । 1982 से, उन्होंने 1986 तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, रे ने बोलपुर के उपचुनाव में कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार के रूप में अनुभवी कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ खड़े होकर राज्य की राजनीति में वापस लौटने की कोशिश की। 1985 में सीट, लेकिन उनकी अलोकप्रियता और राज्य कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग के साथ दुश्मनी के कारण उन्हें लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। [9]

प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने 2 अप्रैल 1986 को रे को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया, जहां उन्होंने सिख विद्रोहियों को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई , हालांकि वहां भी उन पर पुलिस की बर्बरता करने का आरोप लगाया गया, जबकि राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था । एआईएसएसएफ महासचिव हरमिंदर सिंह संधू को बेअसर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने की जिद के कारण प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 8 दिसंबर 1989 को रे को राज्यपाल पद से हटा दिया था। [17]

यूएसएसआर के पतन के बाद, भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार, रे को प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भेजा था ताकि उस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को पिघलाया जा सके जो पूरे शीत युद्ध के दौरान भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा था । वह 1992 से 1996 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। इससे पहले, वह 1991 से 1992 तक चौरंगी सीट से निर्वाचित होकर राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता थे। 1995 में, यह अफवाह थी कि रे आगामी राज्य चुनाव लड़ने के लिए वापस आ सकते हैं , लेकिन राज्य कांग्रेस इकाई के विरोध के कारण ऐसा नहीं हुआ। रे ने 1999 के भारतीय आम चुनाव में उत्तर पश्चिम कलकत्ता सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना आखिरी चुनाव लड़ा, जिसमें तीसरे स्थान पर रहे ।

आपातकाल में भूमिका

1975 से 1977 तक आपातकाल लागू करने में सिद्धार्थ शंकर रे की प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को "आंतरिक आपातकाल" लगाने का प्रस्ताव दिया और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के लिए उद्घोषणा जारी करने के लिए पत्र का मसौदा भी तैयार किया और दिखाया। संविधान के दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कैसे निलंबित किया जा सकता है। हालाँकि वह इस दौरान संजय गांधी और प्रणब मुखर्जी जैसे साथी कांग्रेसियों द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ मुखर थे ।

सेवानिवृत्ति

1996 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 2010 तक, रे कलकत्ता उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अपने कानून अभ्यास में लौट आए ।

रे अपनी शिष्या ममता बनर्जी के कांग्रेस छोड़ने और अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद भी उनके करीबी बने रहे।

6 नवंबर 2010 को 90 वर्ष की आयु में रे की किडनी फेल होने से मृत्यु हो गई राज्य की सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार की कांग्रेस द्वारा रे को पूर्ण राजकीय सम्मान न देने के लिए आलोचना की गई , जैसा कि रे के कट्टरपंथियों को दिया गया था। -निमसिस ज्योति बसु , जिनकी 9 महीने पहले मृत्यु हो गई।

विरासत

माया रे की उचित सहमति से रे की स्मृति में श्री राजेश चिरिमार द्वारा "सिद्धार्थ शंकर रे फाउंडेशन" नामक एक परोपकारी संस्था का गठन किया गया था । सोसायटी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में संलग्न है और श्री सिद्धार्थ शंकर रे का जन्म शताब्दी वर्ष मनाएगी।